ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.21, No2, April – June, 2026/197

ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिकाः जनपद सुल्तानपुर के संदर्भ में

रमा कुमारी राठौर

https://doi.org/ 10.61410/had.v21i2.293

प्रस्तावना :–

ग्रामीण महिलाओं का स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण आधार हैं। ग्रामीण महिलाएं परिवार, कृषि, पशुपालन तथा सामाजिक जीवन में महत्वपूण्ज्ञ भूमिका निभाती है, फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, शिक्षा और आर्थिक अक्सरों तक उनकी पहुंच अभी भी सीमित हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में भी यह स्थिति विभिन्न स्तरों पर देखने को मिलती है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, एनीमिया, कुपोषण सुरक्षित प्रसव तथा स्वास्थ्य जागकरूता जैसी समस्याएं ग्रामीण महिलाओं के विकास में प्रमुख बाधाएं हैं। इन चुनौतियों को कम करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाए ंसंचालित की जा रही है।

सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS), पोषण अभियान, राष्ट्रीय अजीविका मिशन तथा आयुष्मान भारत योजना ने ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं स्वयं सहायता समूहों (SHGS) के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार, बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता से जोड़ा गया है।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में भी ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण से जुड़ी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं यद्यपि सरकारी योजनाओं के विस्तार से संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तथा महिला स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है, फिर भी जागरूकता की कमी, सामाजिक परंपराएं, आर्थिक विषमताएं तथा स्वास्थ्य सेवाआ तक असमान पहुंच जैसी समस्याएं योजनाओं के प्रभाव को सीमित करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जनपद सुल्तानपुर के संदर्भ में इन योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए, ताकि नीति निर्माण एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जा सके।

जनपद सुल्तानपुर की ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तरको सुधारने के लिए केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं वर्तमान समय में योजनाएं महिलाओं स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढावा दे रही है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) :– गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हे गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सके। इसी प्रकार जननी सुरक्षा येाजना **(JYS)** संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करती है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

पोषण अभियान (PoshanAbhiyaan) :– के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण और एनीमिया को कम करने का प्रयास किया जा रहा हैं। आंगमबाड़ी, केन्द्रों द्वारा पोषण संबंधी परामर्श, टीकाकरण तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) :– के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता ग्रामीण महिलाओं को प्रसव पूर्व, जांच टीकाकरण परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति योजना महत्वपूर्ण हैं यह योजना महिलाओं की सुरक्षा, जागरूकता तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती हैं इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार, बचत तथा आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।

सारणी :–सरकारी योजनाएं एवंउनकाप्रभाव–

क0सं0	योजना	उद्देश्य	लाभ
1	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता	पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार
2	जननी सुरक्षा योजना	संस्थागत प्रसव को बढ़ावा	मातृ मृत्यु दर में कमी
3	पोषण अभियान	कुपोषण एवं एनीमिया में कमी	बेहतर पेाषण
4	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता	स्वास्थ्य जागरूकता
5.	मिशन शक्ति	महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण	आत्मविश्वास एवं सुरक्षा
6	स्वयं सहायता समूह	आर्थिक आत्मनिर्भरता	आय में वृद्धि
7	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य सुरक्षा

निष्कर्षः–

वर्तमान सरकारी योजनाएं सुल्तानपुर जनपद की ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण में महत्वपूण्ज्ञ भूमिका निभा रही हैं। हालांकि, इन योजनाओं का अधिक प्रभाव तभी संभव हैं, जब महिलाओं में जागरूकता बढ़े, शिक्षा का स्तर सुधार तथा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र महिला तक पहुँचे। इससे ग्रामीण महिलाओं की समाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थः–

1. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (JIPS) एवं JCP, (2021), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5 2019–21), भारत रिपोर्ट, मुम्बई।
2. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (2024), ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (Rural Health Statistics), नई दिल्ली।
3. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (2024), स्वास्थ्य प्रबंधक सूचना प्रणाली (HMIS) वार्षिक प्रतिवेदन, नई दिल्ली।
4. भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (2024), पोषण अभियन्ता (POSHAN अभियान)–वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, नई दिल्ली।
5. भारतसरकार (2024), प्रधानमंत्री मातृ वेदना योजना–दिशानिर्देश, नईदिल्ली।
6. विश्व स्वास्थ्य संगठन (2023) मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण पर वैश्विक प्रतिवेदन।
7. यूनिसेफ, (2023) भारत में मातृ एवं शिशु पोषण रिपोर्ट।
8. रामकृष्णन, उषा एवंअन्य (2012), भारत में मातृ पोषण सुधार हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप, चुनैतियो एव ंअक्सर।
9. गुप्ता, रेणु एवं अन्य (2016) गर्भवर्ती महिलाओं में मातृ पोषण संबंध ज्ञान एवं दृष्टिकोण का अध्ययन।
10. नमुएन, फुओंगहांग एव ंअन्य (2019), उत्तर–प्रदेश में मातृ पोषक व्यवहार एवं उसके निर्धारिक कारक।
11. जोहरी, मीरा एवं अन्य (2016) भारत में मातृ स्वास्थ्य साक्षरता एवं बालपोषण की स्थिति का अध्ययन।
12. भारत सरकार. योगेन्द्र सिंह –भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन।
13. राम अहूजा–भारतीय समाज, ग्रामीण स्वास्थ्य एव ंमहिला अध्ययन संबंधी शोध पत्र एवं सरकारी रिपोर्ट।

रमा कुमारी राठौर, ईमेल